an>

Title: Need to put in place a mechanism for better co-ordination of matters dealing with disbursement of relief and financial assistance to the poeple in the drought affected states.

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) ः आप सभी को ज्ञात होगा कि देश के कई राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं की वजह से किसानों को काफी कष्ट झेलना पड़ रहा है। कुछ राज्यों में सूखे की गंभीर स्थिति तो कहीं ज्यादा बारिश की वजह से हुई तबाही। सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए प्रयास जरूर कर रही है लेकिन इन राज्यों का जायजा लेने पर ज्ञात हुआ कि प्रशासन में गंभीरता से इस प्रश्न का हल निकालने के लिए और किसानों को मदद करने हेतु वांछित सक्रियता का अभाव है। इस प्रकार की धीमी कार्य प्रणाली से स्थिति के और गंभीर होने की संभावना है। पीने का पानी और जानवरों का खाना और इस स्थिति का आंकलन करने में इस सुस्त रवैये की वजह से संकट की स्थिति और बदतर हो सकती है। आज केंद्र सरकार द्वारा संकटग्रस्त राज्यों को मुहैया कराई गई मदद राशि जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने हेतु प्रशासन में चुस्ती लाना अनिवार्य है। निर्णय प्रक्रिया सिंगल विंडो स्कीम के तहत और सभी संबंधित विभागों का समन्वय रखकर अमल में लाने की आवश्यकता है। अब तक विभागों में समंवय के अभाव से हर एक विभाग मनचाहा निर्णय लेता था और इस वजह से उचित फल प्राप्त करना असंभव था। मेरी सरकार से विनती है कि इस संभाव्य आपदा स्थिति का डटकर मुकाबला करने हेतु और संभाव्य क्षति कम से कम करने के लिए तुरंत उपाय की आवश्यकता सभी स्तरों पर करने की जरूरत है। मार्च, अप्रैल में और जून तक इस गहरे संकट को मिटाने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास हों और पीने के पानी की समस्या की वजह से लोग और जानवर विस्थापित न हो, हम सब इकट्ठा होकर इस सामाजिक अभियान को सफल बना दे और दीर्घकालीन उपायों के सहारे आगे देश को ऐसे संकट का दोबारा सामना करने की नौबत न आये, ऐसा प्रावधान करने की तुरंत जरूरत है।